

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पेश ओम बिरला का लोकसभा में ना जाने का फैसला, 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा होगी

नई दिल्ली

विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यूज एजेंसी ट्विटर ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे।

एजेंसी के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी।

इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन संसद दो बार स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो सकी। शशि थरुर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने



तक सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर 9 मार्च को विचार किया जा सकता है, जो बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा।

इसी दिन सदन में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। गौरतलब है कि विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं और सत्तापक्ष के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि, लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक

तौर पर अधिकतर प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इसके पारित होने की संभावना बेहद कम है। मंगलवार को विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई ने बताया कि यह नोटिस दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 94सी के अंतर्गत औपचारिक रूप से जमा किया गया। कांग्रेस के अनुसार, इस प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़म (द्रमुक) समेत कई विपक्षी

दलों ने इसका समर्थन किया है। हालांकि, तुणमूल कांग्रेस ने अब तक इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार उन्हें सदन में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर नहीं दिया। विपक्ष का कहना है कि इसी कारण उन्हें अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाना पड़ा।

पेंगुइन बोली- कोई भी हिस्सा पब्लिक नहीं किया

राहुल का यह बयान पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस क्लेरिफिकेशन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। पेंगुइन कंपनी ने कहा- अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे मुझे उन पर भरोसा: राहुल गांधी

लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कथित किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशक पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया कि किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने मोबाइल में जनरल नरवणे का 15 दिसंबर 2023 का पोस्ट दिखाया।

उन्होंने कहा कि यह जनरल नरवणे का एक्स पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था, नमस्ते दोस्तों। मेरी किताब अब उपलब्ध है। बस इस लिंक का अनुसरण करें। आनंदपूर्वक पढ़ें। जय हिंद। राहुल ने कहा, सवाल यह है कि या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंग्विन प्रकाशन, लेकिन मुझे पूर्व सेनाध्यक्ष पर भरोसा है, वह झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि किताब

में किए गए कुछ उल्लेख सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं, इसलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब यह तय करना होगा कि सच्चाई कौन बता रहा है। प्रकाशक या पूर्व सेनाध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे ने किताब में जो बातें लिखी हैं, वे सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असहज हैं और इसी वजह से इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोमवार को कहा था कि जनरल नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी, प्रिंट या डिजिटल, पब्लिश, बांटी, बेची या पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। राहुल गांधी ने जिस पोस्ट का जिक्र किया था उसे जनरल नरवणे ने 15 दिसंबर 2023 को एक्स पर साझा किया था।

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में सभी कॉपियों की डिजिटल जांच होगी



32 करोड़ पन्ने ऑन स्क्रीन स्कैन होंगे

नई दिल्ली

सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगी। इस बार 12वीं के 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएंगी। मतलब ये कि इन्हें डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा।

इसके लिए हर छात्र की सभी उत्तरपुस्तिकाओं के हर पन्ने को परीक्षा केंद्र में ही स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। करीब 1 करोड़ कॉपियों के लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। परीक्षक इन डिजिटल कॉपियों की जांच करके ही नंबर देंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग पहले की तरह

कागज पर ही होगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भाद्राज के मुताबिक इस नई व्यवस्था से उत्तर पुस्तिकाओं के ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय और खर्च बचेगा।

शिक्षक अपने स्कूल में रहते हुए ही मूल्यांकन कर सकेंगे, बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मूल्यांकन की अधिक पारदर्शी, तेज और झुटिरहित बनाने के मकसद से बोर्ड ने यह प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है।

सभी कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल तरीके से ही जांचेंगे। मूल्यांकन तेज हो जाएगा, जिससे समय पर परिणाम घोषित हो सकेंगे। कक्षा10 की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां पहले की तरह ही जांचेंगे। सभी 32 हजार स्कूलों को निर्देश कॉपी स्कैनिंग की पूरी तैयारी रखें। टोटलिंग में गलतियां खत्म होंगी, अंकों की गणना ऑटोमेटेड होगी

बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा, जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा: सीएम योगी

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार जो बोलती है, करके दिखाती है। यह जितना करती है, उतना ही बोलती है। योगी ने कहा कि जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उनको बता दूँ कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र में दुल्हंदेपुर स्थित बाबा हरिशंकर दास की कुटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं, जो अवसरवादी रवैया अपनते हैं। जब संकट आता है तब भागवान राम याद आते हैं, बाकी राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं।



मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की वजह से अब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले यह बीमार प्रदेश था। कब कहाँ लूट, हत्या हो जाएगी पता नहीं होता था। बहु-बेटियां सुरक्षित नहीं थी और घर से बाहर गया व्यक्ति अगर शाम तक नहीं लौटता था तो घर वाले अनहोनी की

आशंका से बार-बार फोन करके हालचाल लेते रहते थे। कानून से खिलवाड़ करने वालों को आगाह करते हुए योगी ने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे, तो फायदे में रहोगे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की बात है तो यह कयामत तक नहीं होगा क्योंकि कयामत आने वाली नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की लंबी लड़ाई से लेकर भव्य मंदिर निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए योगी कहा कि राम मंदिर बन गया है न। आज मंदिर अपने निर्धारित स्थान पर बन चुका है। गोला गोकर्णनाथ, लोधेश्वर मंदिर समेत कई मंदिरों के हो रहे कॉरिडोर निर्माण का भी उन्होंने उल्लेख किया।

मणिपुर के उखरुल में पांच दिन के लिए इंटरनेट बंद



उपद्रवियों ने 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर फूँके

इंफाल

मणिपुर में नई सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने उखरुल जिले के लितान सेरेखोंग गांव में 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 10

फरवरी की सुबह 11:30 बजे से अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद हैं। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम लितान सेरेखोंग में हुए एक शराब के नशे में झगड़े से हुई थी, जिसमें तांगखुल नामा समुदाय के स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी।

भारत ने सऊदी अरब में दिखाई स्वदेशी हथियारों की ताकत

नई दिल्ली

भारत ने सऊदी अरब के रियाद में हुए वर्ल्ड डिफेंस शो में स्वदेशी हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेट ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें भारत में बने हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा उद्योगों और रक्षा मंत्रालय की प्रदर्शनी का भी दौरा किया, ताकि उनकी स्वदेशी तकनीक की समीक्षा की जा सके। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेट भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ



रियाद में 8-9 फरवरी को हुए वर्ल्ड डिफेंस शो में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने सऊदी अरब के सहायक रक्षा मंत्री डॉ. खालिद बिन हुसैन अल-बियारी के साथ दोनों देशों के

सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने सऊदी अरब जनरल अर्थारीटी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट के गवर्नर डॉ. फलेह बिन अब्दुल्ला अल-सुलेमान से भी

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी आज विधानसभा में पेश करेंगी बजट



जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार (11 फरवरी) को प्रातः 11 बजे राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट प्रस्तुति से पहले मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट को

अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त, राजन विशाल, शासन सचिव वित्त कुमारपाल गौतम तथा निदेशक वित्त, बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।

एआई से बने वीडियो अब नहीं बचेंगे, सरकार लाई सख्त नियम

डीपफेक वीडियो-फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे सभी एआई ऑडियो-वीडियो लेबल लगाना होगा

नई दिल्ली

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस जैसे एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, स्नेपचैट और फेसबुक को अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। इसके साथ ही डीपफेक वीडियो-फोटो 3 घंटे में हटाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसमें IT रूल्स 2021 में बदलाव किया गया है। बदले हुए नियम 20 फरवरी से



लागू होंगे। इसका ड्राफ्ट सरकार ने 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया था।

नए नियम डीपफेक और एआई से बने कंटेंट को लेबल और ट्रेस करने के लिए हैं। मतलब, अब एआई कंटेंट में साफ लिखना होगा कि यह कंटेंट असली नहीं, एआई वाला है। इससे मिसइन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी।

नई रूल 3(3) के तहत, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई कंटेंट जैसी 'सिंथेटिकली जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन' क्रिएट करने देगा, उसे हर ऐसे कंटेंट पर प्रॉमिनेंट लेबल लगाना होगा। परमानेंट यूनिक मेटाडेटा/आईडेंटिफायर एम्बेड भी करना पड़ेगा।

ये लेबल विजुअल में कम से कम 10% एरिया कवर करेगा या ऑडियो में पहले 10% टाइम में

सुनाई देगा। मेटाडेटा को कोई चेंज, हाइड या डिलीट नहीं कर पाएगा। प्लेटफॉर्मस को टेक्निकल तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि अपलोड होने से पहले ही चेक हो जाए कि ये एआई वाला है या नहीं।

लेबल हटाना या छिपाना अब मुमकिन नहीं: सोशल मीडिया कंपनियां अब एआई लेबल या उसके मेटाडेटा (पहचान की जानकारी) को हटाने या छिपाने की इजाजत नहीं दे सकतीं। एक बार लेबल लग गया, तो उसे वैसे ही रखना होगा।

गंदे और भ्रामक कंटेंट पर लगाय: सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे ऑटोमेटेड टूलस (सॉफ्टवेयर) इस्तेमाल करें, जो एआई के जरिए बनाए गए गैर-कानूनी, अश्लील या धोखाधड़ी वाले कंटेंट को रोक सकें।

हर 3 महीने में चेतावनी देना अनिवार्य: कंपनियों को हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को वॉरनिंग देनी होगी। उन्हें बताया होगा कि अगर उन्होंने एआई का गलत इस्तेमाल किया या नियम तोड़े, तो उन्हें सजा या जुर्माना भुगतान पड़ सकता है।

यूजर्स अब फेक कंटेंट आसानी से पहचान सकेंगे, मिसइन्फॉर्मेशन कम होगी। लेकिन क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, जैसे लेबल लगाना।

इंडस्ट्री के लिए चैलेंज ये होगा कि उन्हें मेटाडेटा और वेरिफिकेशन के लिए टेक इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो ऑपरेटिंग्स को थोड़ा महंगा कर सकता है। लेकिन ओवरऑल, ये एआई मिसयूज रोकने में मददगार साबित होगा।

हिमंता थूटिंग वीडियो विवाद- सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है: सीजेआई

नई दिल्ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो को लेकर CPI(M) और CPI के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सीनियर वकील निजाम पाशा ने मंगलवार को यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मंशन



किया। उन्होंने कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के भाषणों और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है।

निजाम पाशा ने यह भी बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने CPI(M) और CPI नेताओं की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस ने पहले उठाया था वीडियो का मुद्दा

दरअसल, 8 जनवरी को कांग्रेस ने दावा किया कि असम बीजेपी एक्स हैडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा मुसलमानों को गोली मारते दिख रहे हैं।

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपी आकाशदीप को मिली सशर्त जमानत

मुंबई (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को इस केस के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को सशर्त जमानत दी है। आकाशदीप इस मामले में जमानत पाते वाला पहला आरोपी है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी मुंबई नहीं छोड़ेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को तीन हमलावरों ने अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी आकाशदीप करज सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका में आकाशदीप सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था, कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और अभियोजन पक्ष ने हत्या में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की है। याचिका में यह भी कहा गया कि उस पर केवल एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जबकि हत्या की साजिश या वारदात में उसकी सीधी सलिमता साबित नहीं होती। आरोपी की ओर से पेशा वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले की सुनवाई निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना नहीं है और बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखना आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी आधार पर जमानत की मांग की गई थी।

पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई- 4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया

पटना (एजेंसी)। पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई- 4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जो करीब दो घंटे बाद जेपी गोलंबर पर आकर खत्म हुआ। अभ्यर्थी हाथों में ‘शिक्षा मंत्री झूठा है’ और ‘आई तल टीआरआई- 4’ लिखे पोस्टर लेकर नौलिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमाटकी हुई। कई अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि कुछ छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल बीपीएससी ने वर्ष 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई- 4 का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर टीआरई- 4 को टालना चाहती है। कैलेंडर से टीआरई- 4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गई है। पिछले सोमवार को जारी बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 70वीं, 71वीं और 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई), न्यायिक सेवा, आचार्य, तकनीकी और प्रशासनिक पदों सहित 50 से अधिक भर्तियों की संभावित तिथियां दी गई हैं। इस कैलेंडर में विविध शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास और प्रशिक्षण विभागों की भी जिक्र है, लेकिन टीआरई- 4 पूरी तरह नदारद है।

जोधपुर दौरे पर पहुंची थार्डलैंड की राजकुमारी....रातोंरात हो गया शहर का कायाकल्प

जोधपुर (एजेंसी)। थार्डलैंड की राजकुमारी सिरीनानवारी नरीरत्ना राजकन्या राजस्थान के जोधपुर दौरे पर है। रविवार को जोधपुर के एयरपोर्ट स्टेशन से राजकन्या उम्मेद भवन पैलेस पहुंचीं यहां से रात को घंटाघर और भीतरी शहर के हवेली में पहुंचीं। जहां पर उन्होंने डिनर किया। सोमवार को उनका जोधपुर के मेहरानगढ़ किला जयवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जाने का कार्यक्रम है। थार्डलैंड की राजकुमारी के स्वागत में जोधपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। उनके जोधपुर दौरे को देखकर पुलिस ने भारी सुरक्षा और यातायात के बंदोबस्त किए गए हैं। वीटीआईपी मूवमेंट को लेकर शहर में कई जगहों पर यातायात रोक दिया गया। इसके चलते लोग जाम में भी फंसे नजर आए। जहां जोधपुर के घंटाघर बाजार में भी आम दिनों में जहां अतिरुमण और टेलों की भीड़भाड़ रहती है। वह भी राजकुमारी के दौरे के कारण साफ सुरुरा नजर आया। इस लेकर भी शहर के लोगों ने सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि जब एक दिन में पूरी तरह से व्यवस्था बदल सकती है, तब बाकी दिनों में घंटाघर का बाजार अतिरुमण, जाम और पार्किंग की वजह से क्यों बर्हाल नजर आता है।

सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुनवाई टली.... अब बुधवार को फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसजी) कैप्टन नटराज ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी अवधि के स्थगन की मांग स्वीकार नहीं कर मामले को बुधवार के लिए सुबूद किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि इस मामले में अब तक क्या प्राप्ति हुई है। दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था और केंद्र सरकार से इस संबंध में उचित निर्णय लेने को कह दिया था। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त को बताया गया कि वांगचुक को हिरासत के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अदालत को आशवासन दिया कि उनकी सहेत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछास में 24 सितंबर को हुई हिंसा में चार लोगों की जान गई थी। यह हिंसा लंह में लदाख को छठी अनुसूची का जन्म और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे। बाद में, 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लदाख में हिसक विविध प्रस्थान भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। इसके अलावा, प्रशासन ने चार लोगों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।

क्या रूस छोड़कर अमेरिका से तेल खरीदेगा भारत, मंत्री पीयूष गोयल ने स्थिती स्पष्ट कर दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर देश का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका से कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की खरीद भारत के रणनीतिक हितों के अनुकूल है, क्योंकि इससे भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाने का अवसर मिलता है। गोयल के अनुसार, व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य दो देशों के बीच कारोबार के रास्ते को सुगम बनाना और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पादों को विशेष पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 18 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क होने के बावजूद, यह समझौता भारत को अन्य विकासशील देशों के मुकाबले बढ़त दिलाता है, जो वैश्विक बाजार में भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

भारत की भविष्य की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत को अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर, मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने इस आंकड़े को



काफी रूढ़िवादी बताया और कहा कि 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले देश के लिए यह राशि बहुत कम है। गोयल ने स्पष्ट किया कि अकेले विमानन क्षेत्र के लिए ही भारत को कम से कम 100 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत वर्तमान में अन्य देशों से जो 300 अरब डॉलर का सामान आयात कर रहा है, उसे आसानी

से अमेरिकी बाजार की ओर मोड़ा जा सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

रणनीतिक पहलुओं पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि व्यापार समझौता यह तय नहीं करता कि कौन खरीदार किससे और क्या खरीदेगा। तेल या अन्य संसाधनों की खरीद के फैसले मुख्य रूप से घरेलू खरीदारों द्वारा ही लिए

महिला बोली सॉरी! गलती से मैसेज पहुंच गया, व्यक्ति ने शुरु की चैटिंग, गवां दिए 70 लाख

नई दिल्ली (एजेंसी)। साइबर से 70 लाख रुपए उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु स्थित प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 50 साल के एक व्यक्ति के पास टेलीग्राम पर एक महिला का मैसेज आया। महिला ने अपना नाम प्रिया बताया, इसके बाद उसने कहा कि वह किसी राहुल नाम के व्यक्ति को मैसेज कर रही थीं और गलती से विक्टिम को पास पहुंच गया। महिला ने सॉरी कहकर मैसेज इग्नोर करने को कहा। इसके बाद विक्टिम ने चैटिंग जारी रखी। फिर दोनों के बीच वॉट्सएप नंबर शेयर किए गए। फिर महिला ने कहा कि वह लंदन बेस्ड कंपनी में काम करती है और अपने परिवार का बिजनेस चलाती है। लंबी चैटिंग के बाद महिला ने विक्टिम का भरोसा जीत लिया।

रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर चर्चा शुरू कर दी। महिला ने बताया कि बीते पांच साल में उन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई

औवेसी ने सीएम सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की... वीडियो को लेकर विवाद

हैदराबाद (एजेंसी)। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन औवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। औवैसी ने यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट हो चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में औवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसमें से कई बयान अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

हाल के महीनों में मुख्यमंत्री सरमा ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और



तेज किया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ाना है। औवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ल बनाम न्यूनिन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले को साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की

रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की

भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं यह बातना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया हालिया वीडियो, जिस वीडियो को एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें सरमा को हथियार से लेस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें जम्मू और कश्मीर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और पॉइंट ब्लैंक शॉट और कोई दया नहीं जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनाना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।

खामियों से भरी मतदाता सूची से ही चुनाव कराना चाहती हैं ममता बनर्जी:भाजपा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम

बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और गलतियों से भरी मतदाता सूची के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी दल नुटिएणू वोटर लिस्ट के साथ चुनावी मतों के लिए बेवबाह है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद



बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुईं और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों इन मामलों की जांच कर रही है, लेकिन स्थानीय पुलिस साक्ष्यों को मिटाने के प्रयासों में जुटी है। वहीं, भाजपा के दिग्गज नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने को याचिका दायर किए जाने को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार जब भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाती है, उसे हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी अपीलों का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं होता। घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार लोगों को न्याय देने में विफल रही है, जिसके कारण आम

जनता को बार-बार अदालतों की शरण लेनी पड़ती है। दिलीप घोष ने ममता सरकार पर गुथैकण और विपक्षी दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के गांवों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और विपक्षी कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में विशेष समुदाय के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन टीएमसी के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। इन बयानों के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है।



मॉडल स्कूल बनेड़ा के दो छात्रों का राज्य पुरस्कार के लिए चयन



स्मार्ट हलचल | बनेड़ा

उपखण्ड मुख्यालय स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के दो छात्रों का स्काउट गाइड के राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। मॉडल स्कूल प्रधानाचार्य भरत देव धाभाई ने बताया कि स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर में 11 फरवरी को आयोजित होने वाले राज्य पुरस्कार समारोह में स्थानीय विद्यालय के यूनिट लीडर दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में दो छात्र रौनक गारू व आयुष सिंह गौड़ सम्मिलित होंगे। स्थानीय स्काउट गाइड संघ बनेड़ा के सचिव सुरेश चंद्र शर्मा व समस्त स्टाफ सदस्यों ने राज्य पुरस्कार में सम्मिलित होने वाले दोनों छात्रों को शुभकामनाएं दी है।

वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी का निधन

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा



शहर के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी का मंगलवार दोपहर 77 वर्ष की आय में निधन हो गया। वे पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा के पत्रकारिता और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जोशी जी ने अपने सुदीर्घ करियर में कई राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तरीय समाचार पत्रों एवं चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकारिता के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। उन्होंने लंबे समय तक संस्कृत विद्यापीठ विद्यालय में अध्यापन कार्य कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

स्व. जोशी अपने सहज, सरल और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। उनका जाना भीलवाड़ा मीडिया जगत के लिए एक अग्रणीय क्षति है।

पंडित अशोक शर्मा का नागरिक अभिनंदन

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

चंद्रशेखर आजाद नगर सब्जी मंडी चौराहा पर पंडित अशोक शर्मा के पंचवर्षीय पार्षद का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर समस्त वार्ड वासियो द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया । विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि जब भी जनहित के काम बताये गए उस कार्य को करने का पूर्ण प्रयास किया एवं वह कार्य हुए इस मौके पर नि वर्तमान पार्षद का साफा बंधवाकर माला पहना कर मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया दिनेश गोड़ ने बताया कि नि वर्तमान पार्षद ने अपने उद्घोहन में बताया कि 5 वर्षीय पार्षद कार्यकाल से सेवा मुक्त हो रहे हैं । सार्वजनिक कार्य, जनहित कार्य, समाज सेवा के कार्य से मुक्त नहीं हो रहा हूँ यह सभी कार्य करने के लिए सदैववार्ड वासियो के लिए तैयार रहेंगे सदैव सहयोग करने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार जताया एवं इस मौके पर समस्त वार्ड वासियो ने आगे भी नि वर्तमान पार्षद को



स्नेह, समर्थन, पूर्ण सहयोग करने विश्वास दिलाया उपरोक्त कार्यक्रम मे विक्रम सिंह राठौड़, राजेंद्र माहेश्वरी, दिनेश गोड़, विष्णु अग्रवाल, पूरन सिंह पुरावत, दीपक सुवालका, महेश शर्मा, अरुणाफ हुसैन अंसारी, अभिषेक आर्य, रवि सेन, नरेंद्र सिंह, पिपूष दाधीच, गोपाल शर्मा, शिव चोंडक, राजेश शर्मा, सोम शर्मा, दीपक शर्मा, इंद्र सिंह, चंदु डीजे, हरि चरण शर्मा, देव किशन शर्मा, आयुष शर्मा, मथुरा लाल दसोरा, आदि कई वार्ड वासी उपस्थित थे।

एसडीएम कॉलेज महिला आश्रम भीलवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विशेष शिविर आयोजित

अच्छा स्वास्थ्य असली समृद्धि है जो जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक: रश्मि पारीक डायरेक्टर विभा माथुर ने वितरित किए स्वयं सेविकाओं को प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र गए



स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय महिला आश्रम भीलवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन संपन्न करवाया गया। आयोजन के अध्यक्षता प्रचार्य डॉ रजनीश शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अंजना वैष्णव व सह अधिकारी सुश्री ज्योति शर्मा व सुश्री खुशी नाथावत के द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कश्मीर भट्ट के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करवा कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। सात दिवसीय विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य सेवा से सशक्त

द्वारा स्वयं सेविकाओं को सेवा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। भट्ट के व्याख्यान का मुख्य विषय राष्ट्र निर्माण में युवा का योगदान व राष्ट्रीय एकता व नागरिक शिष्टाचार से युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण को बढ़ावा दिया और स्वयंसेविकाओं द्वारा पौधारोपण व स्वच्छता अभियान चलाया गया और श्रमदान करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलकांत शर्मा के व्याख्यान में स्वयं सेविकाओं को स्त्री स्वास्थ्य, जल्दी सोये जल्दी जागे के विचार द्वारा स्वयंसेविकाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और स्वस्थ जीवन से खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित किया गया आयुर्वेदिक विज्ञान की महत्व और आरोग्य का सूत्र देते



हुए महोदयजी ने अपने विचार व्यक्त किए है। मुख्य वक्ता से सुश्री रश्मि पारीक द्वारा स्वयं सेविकाओं को स्वास्थ्य और समृद्धि स्वास्थ्य और समृद्धि का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने का आर्थिक सुरक्षा व जीवन को संतुष्टि का एक संयुक्त रूप का उद्देश्य दिया। स्वास्थ्य ही धन है अच्छा स्वास्थ्य असली समृद्धि है जो जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। वक्ता श्रीमती वसुंधरा सक्सेना द्वारा आहार में पोषण को संतुलित कर स्वयं सेविकाओं को स्वर्गीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वक्ता श्रीमती श्वेता सोडाणी द्वारा मुख्य बजट सत्र 2025-26 सभी स्वयंसेविकाओं को बजट में विद्यार्थी उपयोगी वार्ता द्वारा आर्थिक समृद्धि और

व्यवसायिक प्रबंधन द्वारा मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार सात दिवस तक राष्ट्रीय सेवा योजना गीत, वंदे मातरम, गांव भ्रमण, स्त्री स्वास्थ्य, नशा मुक्ति अभियान, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता पर पोस्टर,स्लोगन व रैली व नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवा कर विशेष शिविर को संपन्न करवाया गया। महिला आश्रम संस्था की सचिव श्रीमती वंदना माथुर ने स्वयं सेविकाओं की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही डायरेक्टर श्रीमती विभा माथुर द्वारा स्वयं सेविकाओं को कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए और और उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की।

टायर फटने गाड़ी पलटी, सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकराई, कोटड़ी एसडीएम व चालक घायल



प्राथमिक उपचार के बाद उपखंड अधिकारी को गंभीर हालत होने पर भीलवाड़ा चिकित्सालय रैफर किया गया, वहीं सूचना मिलने पर मौके पर बड़लियास नायब तहसीलदार मदनलाल शर्मा, एएसआई गोपाल सिंह, आकोला व जीवाखेड़ा पटवारी मौके पर पहुंचे । दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों

की भारी भीड़ जमा हो गई ।।

चिकित्सालय में नहीं मिला डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर ने किया उपचार

हादसे में घायल हुई उपखंड अधिकारी तानिया रिणवा व चालक को सवाईपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य



केंद्र पर लेकर आये लेकिन यहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते नर्सिंग ऑफिसर को उपखंड अधिकारी का प्राथमिक उपचार करना पड़ा वह उनको भीलवाड़ा रैफर किया । वहीं ग्रामीण में चर्चा है कि अगर उपखंड के मुखिया के इलाज के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें वापस हटाना पड़ता है ।

सड़क किनारे लगे पोल बन रहे हादसे का कारण

क्षेत्र में नई विद्युत लाइन डालने के दौरान ठेकेदार द्वारा विद्युत पोल को सड़क से महज कुछ दूरी पर ही लगा दिया जाता है, जिसके चलते आए दिन हादसे देखने को मिल रहे हैं । इसको लेकर रेडवास विद्युत ग्रीड का शिलान्यास करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर से भी पत्रकारों ने इस संबंध में सवाल किया, जिस पर ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा था कि उन्होंने इस संबंध में गाइड लाइन जारी कर रखी है कि सड़क के किनारे विद्युत पोल ना लगाएं क्योंकि जब भी कोई सड़के चौड़ी होती है तो उन्हें वापस हटाना पड़ता है ।

भीनमाल माघ कॉलोनी में हुई चोरी की घटना पुलिस पहुंची मौके पर



स्मार्ट हलचल

भीनमाल पुलिस ने पहुंचकर किया मौका सुआयना सीसीटीवी कैमरा के आधार पर की जा रही जांच चोरी ने एक जैन घर मंदिर व सून पड़े 3 मकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया अंजाम मोहरले वासियों ने बताया कि माघ कॉलोनी में एम भंवर जैन का मकान है उसमें चोरी हुई उनका परिवार जो वर्तमान में मुंबई में रहता है उनके घर के ताले टूटे है।

उनके पड़ोस के मकान के पास

में जयंती शर्मा एवं उसके भाई विनोद शर्मा का मकान है उनके भी ताले टूटे दोनों भाई अपने परिवार सहित कल एक शादी समारोह में पाली गए हुए थे उनके मकान के भी ताले टूटे एवं अंदर से चोरी हुई एवं सामने ही एक जैन मंदिर देगसर है उसके भी ताले टूटे वहां पर कोई चोरी नहीं हुई सुबह पुजारी के आने पर पता चला। तीन मकान मालिकों के आने के बाद पता चला कि कितनी चोरी हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका सुआयना किया एवं जांच शुरू की ।

राजसेस महाविद्यालयों में सविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनर्संरचना की माँग

स्मार्ट हलचल | शाहपुरा

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की शाहपुरा महाविद्यालय इकाई द्वारा आज राजसेस (राजसेस) महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि माननीय विधाकर्म महोदय के माध्यम से दिया। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजसेस योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के विपरीत है। इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अध्येस संरचना एवं संसाधन, शोध एवं नवाचार की संभावनाओं का न होना तथा सविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था को मुख्यालय बनाया जाना जैसे विचार न्यायमूर्ति बेरी जी की वैचारिक विरासत का अभिन्न अंग रहे हैं। 'बेरी गौव अवार्ड' से सम्मानित किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रतिभा के परिचारजनों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों एवं शुभचिंतकों द्वारा उन्हें हार्दिक बधाइयों एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं।



राजसेस योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में 71 अतिरिक्त राजसेस महाविद्यालय खोले जा चुके हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। इनमें से लगभग 260 राजसेस महाविद्यालयों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख

किया गया कि विधानसभा चुनाव-2023 के पश्चात गठित राज्य सरकार द्वारा राजसेस महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशें अब तक न तो सार्वजनिक की गई हैं और न ही लागू की गई हैं। महासंघ ने यह भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के माध्यम से राजसेस नियम-2023 में परिवर्तन कर पाँच वर्षों के लिए 28500 रुपये के नियत वेतन पर सविदा टीचिंग एसोसिएट एवं

अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। महासंघ के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी, असुरक्षित एवं नीति-विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के सर्वथा विपरीत है। महासंघ ने राज्य सरकार से माँग की कि राजसेस महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए, राज्य में संचालित सभी राजसेस महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएँ तथा सविदा नियुक्तियों की प्रस्तावित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। महासंघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो संपादन को लोकतांत्रिक एवं आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने के लिए निवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्णा जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

कल्याणपुरा रोड पर बन रही 2 लाख लीटर क्षमता की जल टंकी, अप्रैल तक मिलेगी पानी की किल्लत से राहत

स्मार्ट हलचल | मंगरोप

कस्बे के कल्याणपुरा रोड पर चम्बल विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करीब 2 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली ऊंची जल टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है।यह टंकी लगभग 22 मीटर ऊंची बनाई जा रही है,जिससे आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त दबाव के साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।जल टंकी का निर्माण कार्य 8 नवम्बर से प्रारंभ किया गया था।विभाग द्वारा इसकी मजबूती और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है,ताकि यह टंकी लंबे समय तक सुरक्षित एवं टिकाऊ बनी रहे।निर्माण स्थल पर वर्तमान में 2 कुशल कारीगरों सहित कुल 7 मजदूर कार्यरत हैं,जो निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य को अंजाम दे रहे हैं।चम्बल विभाग के अनुसार,यह जल टंकी आगामी अप्रैल माह तक पूरी तरह बनकर तैयार



हो जाएगी।इसके पूर्ण होने के बाद मंगरोप कस्बे एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।स्थानीय लोगों ने भी इस योजना को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा बताया है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मनाया शवित दिवस, बच्चों को पिलाई आयरन सिरप ‘गर्भ की पाटशाला’-चैनल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पढ़ाया जा रहा स्वस्थ मां व गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा का पाठ

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। शिशुओं और आमजन महिलाओं, शाशुओं और आमजन को स्वस्थ मातृत्व व सुरक्षित शिशु जन्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग द्वारा मंगलवार को जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को आयरन सिरप पिलाई गई तथा गर्भवती महिलाओं को एलईडी स्क्रीन टीवी के माध्यम से ‘गर्भ की पाटशाला’ यूट्यूब चैनल के जरिए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीयां दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक आईईसी डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चैनल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिकाधिक गर्भवती महिलाएं जागरूक होकर समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ



उठा सकें। सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निरामय राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मदद मिल रही है। चैनल पर पूरक आहार, एनीमिया के लक्षण एवं रोकथाम, गर्भावस्था के दौरान सावधानियां, स्तनपान की उपयोगिता तथा पीटिक आहार जैसी महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा दी जा रही हैं। मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्र सुवाणा द्वितीय का जिला स्तर से डीपीसी-आईईसी अशोक कुमार प्रजापत एवं डीपीसी-आशा बलबीर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को दी जा रही स्वास्थ्य

सेवाओं की जानकारी ली गई तथा बच्चों को आयरन सिरप पिलाई गई। इस दौरान डीपीसी आईईसी ने आशा बहनों व सहायिकाओं को गर्भ की पाटशाला चैनल के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में गर्भवती महिलाओं तक स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारीयां का प्रचार प्रसार करने को कहा। इस दौरान बीएचएस रतन दाधीच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चन्दा सेन, सहायिका सीमा कोर, आशा, नीतू टेलर सहित स्थानीय महिलाएं उपस्थित रही। डीपीसी (आईईसी) अशोक कुमार प्रजापत ने बताया कि राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत गर्भवती महिलाओं को मां व गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, देखभाल

और पोषण से जुड़ी उपयोगी जानकारी सरल, सहज और रोचक भाषा में उपलब्ध कराने के लिए ‘गर्भ की पाटशाला’ यूट्यूब चैनल का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अब घर बैठे ही स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक जानकारीयां प्राप्त हो रही हैं। डीपीसी (आशा) बलबीर ने बताया कि ‘गर्भ की पाटशाला’ चैनल पर रोचक फिल्मों और डायग्राम के माध्यम से गर्भावस्था की पहचान, एनीमिया प्रबंधन, गर्भधारण पूर्व परामर्श, पोषण, सुरक्षित गर्भपात, सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव सहित गर्भावस्था जैसी जानकारीयां सरल भाषा में दी जा रही हैं। चैनल के माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल, कंगारू मदर केयर, पूरक आहार, स्तनपान, बच्चों में अंतर रखने के उपाय तथा आईयूसीडी से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। चिकित्सा विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे ‘गर्भ की पाटशाला’ यूट्यूब चैनल से जुड़कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारीयां प्राप्त करें और स्वयं व अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाएं।

आखिर क्यों चर्चा में है खेजड़ी बचाओ जन-आंदोलन



सुनील कुमार महला

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हजारों पर्यावरण प्रेमियों, संतों और बिश्नोई समाज के लोगों का विशाल 'महापड़ाव' शुरू हुआ। इस दिन बीकानेर के बाजार पूरी तरह बंद रहे और स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। इसके अगले दिन, 3 फरवरी 2026 को, कलेक्ट्रेट के सामने 363 संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर 'आमरण अनशन' प्रारंभ किया। यह संख्या ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान की स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से चुनी गई थी।

इन दिनों राजस्थान में खेजड़ी बचाओ जन-आंदोलन खास चर्चा में है। दरअसल, खेजड़ी बचाओ जन-आंदोलन राजस्थान के राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा एक जन-आंदोलन है। वास्तव में यह आंदोलन सोलार कंपनियों द्वारा पेड़ों की कटाई के कारण चर्चा में आया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि राजस्थान के बीकानेर और आसपास के इलाकों में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए कंपनियां बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई कर रही हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि पकड़े जाने के डर से पेड़ों को रात के अंधेरे में काटकर जमीन में दबा दिया जाता है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें स्पष्ट हैं। वे पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं। इसके साथ ही राज्य में एक प्रभावी 'ट्री प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने की मांग की जा रही है, जिसमें अवैध कटाई पर भारी जुर्माने (₹.1 लाख तक) और जेल की सजा का प्रावधान हो। आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऐसी जमीनों का ही आवंटन किया जाए, जहां पहले से हर-भरे पेड़ मौजूद न हों।

यहां पाठकों को बताना जरूरी है कि इस आंदोलन की मुख्य और प्रभावी शुरुआत हाल ही में 2 फरवरी 2026 को राजस्थान के बीकानेर जिले से हुई। हालांकि बीकानेर कलेक्ट्रेट और करणीसर भाटियान क्षेत्र में पिछले लगभग एक महीने से शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में इसे 'महा-आंदोलन' का रूप मिला।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हजारों पर्यावरण प्रेमियों, संतों और बिश्नोई समाज के लोगों का विशाल 'महापड़ाव' शुरू हुआ। इस दिन बीकानेर के बाजार पूरी तरह बंद रहे और स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। इसके अगले दिन, 3 फरवरी 2026 को, कलेक्ट्रेट के सामने 363 संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर 'आमरण अनशन' प्रारंभ किया। यह संख्या ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान की स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से चुनी गई थी। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5 और 6 फरवरी 2026 को आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच राज्य के उद्योग मंत्री दी. के. बिश्नोई धरना स्थल पर पहुंचे। सरकार की ओर से जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर तत्काल लिखित प्रतिबंध लगाने तथा विधानसभा में सख्त 'ट्री प्रोटेक्शन एक्ट' लाने के आश्वासन के बाद आमरण अनशन समाप्त किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस जन-आंदोलन का मुख्य केंद्र बीकानेर रहा, लेकिन इसकी गूंज पूरे पश्चिमी राजस्थान(जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर) में विशेष रूप से सुनाई दी। इस आंदोलन में न केवल राजस्थान, बल्कि हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तथा हनुमान बेनीवाल जैसे प्रमुख नेताओं का भी समर्थन मिला, जिससे यह आंदोलन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा।

फिलहाल आमरण अनशन समाप्त हो चुका है, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक विधानसभा में कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक उनका प्रतीकात्मक धरना यानी 'महापड़ाव' जारी रहेगा। उनकी मांग



है कि खेजड़ी कटाई पर लगाया गया प्रतिबंध पूरे राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

यहां पाठकों को यह भी बताना आवश्यक है कि खेजड़ी संरक्षण का इतिहास राजस्थान की मिट्टी में गहराई से जुड़ा हुआ है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वर्ष 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने हरे पेड़ों की बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन बलिदानियों में 69 महिलाएं और 294 पुरुष शामिल थे। खेजड़ली (जोधपुर) का यह बलिदान, वर्ष 1730 ईस्वी (विक्रम संवत् 1787) में घटित, विश्व इतिहास की सबसे महान पर्यावरण संरक्षण घटनाओं में गिना जाता है। यह पेड़ों की रक्षा के लिए दिया गया पहला और सबसे बड़ा सामूहिक बलिदान माना जाता है।

इतिहास बताता है कि जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल के निर्माण हेतु चूना पकाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। इसके लिए उनके कार्दि गिरधारी दास सैनिकों के साथ खेजड़ली गांव पहुंचे और खेजड़ी के हरे पेड़ों को काटने लगे। इसका अमृता देवी बिश्नोई ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने सैनिकों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक नारा दिया-सिर साठे रूँछ रहे, तो भी सस्तो जाण। अर्थात यदि सिर कटने के बाद भी एक पेड़ बचता है, तो यह सौदा भी सस्ता ही समझा जाना चाहिए।

पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी सबसे पहले खेजड़ी के पेड़ से लिपट गईं। सैनिकों ने पेड़ के साथ उन्हें भी काट दिया। उनके बाद उनकी तीन बेटियाँ-आसू, रत्नी और भागू-और फिर उनके पति ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। यह दृश्य देखकर पूरे गांव और आसपास के 84 गांवों के लोग उमड़ पड़े और एक-एक करके पेड़ों से लिपटते चले गए। जब महाराजा अभय सिंह को इस भीषण नरसंहार की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पेड़ों की कटाई रुकवाई और भविष्य के लिए एक ताम्रपत्र यानी राजकीय आदेश जारी किया, जिसमें बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में कभी भी हरे पेड़ न काटे

जाने का निर्देश दिया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि आधुनिक काल का 'चिपको आंदोलन', जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसी खेजड़ली बलिदान से प्रेरित माना जाता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी के नाम पर 'अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार' (राष्ट्रीय पुरस्कार) भी प्रदान करती हैं। खेजड़ली गांव में आज भी एक भव्य शहीद स्मारक स्थित है, जहां हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र 'वृक्ष मेला' आयोजित किया जाता है।

अंत में यह कहना उचित होगा कि खेजड़ी का केवल पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। यह आंदोलन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम 'प्रोसोपिस सिनेररिया' है। इसे 'रैगिस्तान का कल्पवृक्ष' कहा जाता है और यह थार मरुस्थल की पारिस्थितिकी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया था। इसका उद्देश्य थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण को बढ़ावा देना था। यदि हम खेजड़ी वृक्ष से जुड़े आंकड़ों की बात करें, तो सरकार या किसी अन्य विनवसनीय स्रोत द्वारा राज्य में खेजड़ी के कुल वृक्षों की वर्तमान आधिकारिक संख्या का कोई विस्तृत और ताजा डेटा औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ हालिया रिपोर्टों और विधायकों के बयानों से इसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान विधानसभा में एक स्थानीय विधायक ने यह बयान दिया कि पश्चिमी राजस्थान में पिछले 15 वर्षों में लगभग 26 लाख से अधिक खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं और भविष्य

में करीब 50 लाख खेजड़ी पेड़ों की कटाई की तैयारी बताई जा रही है। ये आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि हजारों से लाखों की संख्या में खेजड़ी वृक्ष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका अस्तित्व गंभीर खतरे में है। हालांकि, यहां राहत की बात यह है कि खेजड़ी संरक्षण के प्रयास भी जारी हैं। इसी क्रम में पाठकों को जानकारी देना आवश्यक है कि एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के अनुसार राज्य में सोलर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2028 तक 10 लाख (एक मिलियन) नए खेजड़ी वृक्ष लगाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में खेजड़ी की कुल संख्या बढ़ाना है।

आज भी पश्चिमी राजस्थान में लाखों खेजड़ी के पेड़ मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इन्हें काटा जा चुका है और भविष्य में कटाई की आशंका भी बनी हुई है। वास्तव में खेजड़ी बचाओ आंदोलन राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए चल रहा एक पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन है। इसका मूल कारण खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई और उससे हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ जन-आक्रोश है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग कानूनी सुरक्षा और प्रभावी रोक की है। सामाजिक और राजनीतिक समर्थन, आमरण अनशन तथा सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों के कारण यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि मरुस्थल की जीवनरेखा है। इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य है। वास्तव में खेजड़ी ही नहीं, सभी वृक्षों का संरक्षण संभव है और इसमें असंभव कुछ भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अंधाधुंध कटाई पर सख्त रोक लगाना आवश्यक है। खाली पड़ी सरकारी भूमि, खेतों की मेड़ों और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर खेजड़ी के नए पौधे लगाने का अभियान चलाया जाना चाहिए। नए पौधों के रोपण को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में खेजड़ी संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कोटों, जैसे 'ग्लोबोटम्स' (दीमक), और विभिन्न रोगों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित जैविक उपचार किए जाने चाहिए। खेजड़ली बलिदान से प्रेरणा लेकर समुदाय को संगठित करना और संरक्षण के प्रयासों को बिश्नोई पंथ जैसी परंपराओं से जोड़ना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पशु चराई पर नियंत्रण जरूरी है। खेजड़ी की वृद्धि दर बढ़ाने और उसे जलवायु परिवर्तन के दुष्परभावों से बचाने के लिए उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों पर शोध किया जाना चाहिए। खेजड़ी के आसपास जल संचयन की पारंपरिक विधियों, जैसे टांका और खडीन, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सूखे के समय भी इन पेड़ों को पर्याप्त नमी मिल सके।अति-दोहन पर रोक लगाने के साथ-साथ खेजड़ी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और पंचायतों को पुरस्कार और आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यदि हम पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति सचेत और जागरूक रहेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम वृक्षों को बचाने में सफल हो सकते हैं। (प्रोलास राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

किसानों की आशंकाएं

बीते शनिवार जारी किए गए भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते के प्रारूप को लेकर उठ रहे सवालोंने न फिर उस मूलभूत सवाल को पुख्ता किया है कि मुक्त व्यापार समझौते की कीमत कौन चुकाएगा? साथ ही यह भी कि इसका लाभ किसे मिलेगा? इस समझौते से जुड़ी आशंकाओं को लेकर कुछ किसान संगठन आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। निस्संदेह, उनकी आशंकाएं सिर्फ सोयाबीन तेल, सूखे अनाज और सेब पर आयात शुल्क में छूट को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और भारतीय कृषि के भविष्य को लेकर भी हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि किसान हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। निस्संदेह, कागजों पर तो ये आश्वासन राहत देने वाले लगते हैं, लेकिन व्यवहार में किसानों की आशंकाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ व न्यूजीलैंड के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के कारण सस्ते अयात में भारी वृद्धि हुई, फलतः कमजोर किसानों की दशा खराब हुई। निर्विवाद रूप से भारी संखिदी प्राप्त अमेरिकी सेब से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण होगा। हिमाचल के सेब उत्पादक संगठनों का कहना है कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कमिए गए हैं। 25 प्रतिशत करना व न्यूनतम आयात मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम करने से यह स्वदेशी प्रीमियम सेवा के दाम पर बाजार में बिकने लगेगा। जिसके चलते भारतीय उपभोक्ता समान मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी सेब को तरजीह देंगे। साथ ही सेब का कोल्ड स्टोरेज में संग्रह करना अलाभकारी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि कृषि और उध्ध उद्योग संरक्षित रहेंगे। जबकि संयुक्त समझौते में कृषि और खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर शुल्क कम करने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है। कम आय, बढ़ती लागत और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे किसानों को इन गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता चाहिए। यही वजह है कि कई किसान संगठनों, विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद के समक्ष रखा जाए। निस्संदेह, यह मांग तार्किक है क्योंकि व्यापार समझौते भी घरेलू कानूनों की तरह ही आजीविका को गहराई तक प्रभावित करते हैं। कृषि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मजबूत घरेलू समर्थन, उचित मूल्य, सब्सिडी, बुनियादी ढांचे और जोखिम संरक्षण दिए बिना, बाजारों को खोलने के कदम छोटे और सीमांत किसानों पर भारी पड़ सकते हैं। इसी फिक्र के चलते हड़ताल एक चेतावनी है। यदि सरकार का मानना है कि यह समझौता वास्तव में किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है तो उसे पारदर्शिता, संसदीय बहस और सार्थक परामर्श के माध्यम से इसे साबित भी करना चाहिए। अन्यथा, सुधारों की कहानी एक बार फिर देश के अन्नदाता की चिंताओं को दूर करने में विफल रहेगी। इसी तरह देश के सेब उत्पादकों को भी आश्वस्त करना होगा कि उनके सेब की खुशबू बरकरार रहेगी।

सूक्ति

मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है – चाणव्य
आशा कभी आपको छोड़कर नहीं जाती है, आप इसे छोड़ते है – जॉर्ज वीनवर्ग
अज्ञानता और विचार हीनता मानवता के विनाश के दो सबसे बड़े कारण है – जॉन टिलोटसन



सनत जैन

लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आसन है, जो सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान एवं जिम्मेदारी का प्रतीक है। संविधान में परिभाषित है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन का संचालन करेगा। दोनों ही सदन में सभी सदस्यों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी अध्यक्ष और सभापति की होती है। हालािया घटनाक्रम ने इसी धारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है।विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। पिछले कई सत्रों से लोकसभा में विपक्ष आरोप लगाता रहा है, उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बोलने के पहले तरह-तरह से उन्हें रोका जा रहा है। सदन



योगेश कुमार गोयल

हर साल 10 फरवरी को मनाया जाने वाला 'विश्व दलहन दिवस' हमें यह सोचने का अवसर देता है कि जिन दालों को हम रोजमर्रा में मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच संतुलन की एक गहरी कड़ी हैं। खेतों से लेकर थाली तक की यह यात्रा केवल भोजन भर की नहीं है बल्कि इसमें पोषण, पर्यावरण, कृषि और भविष्य की खाद्य सुरक्षा के सूत्र छिपे हैं। वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम 'विश्व की दलहन: सापेक्ष से उत्कृष्टता की ओर' इसी सच्चाई की रेखांकित करती है कि छोटे से दिखने वाले बीज किस तरह वैश्विक समाधान बनकर उभर रहे हैं। यह दिवस खाद्य एवं कृषि संतुलन के नेतृत्व में विश्वभर में मनाया जाता है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा

के अंदर सदस्यों को बोलने की जो स्वतंत्रता थी, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसे संवैधानिक और परंपरागत अवसर पर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलना वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया। इन्ने असंतोष को आर और पार की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जाती है। जबकि विपक्ष को सवालों और नियमों का हवाला देकर बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूक रहा है, कि आसदी द्वारा सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का यह तर्क कि 'सदन नियम और परंपरा से चलेगा' अपने आप में सही है, लेकिन सवाल यह है, कि क्या ये नियम सबके लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में विपक्ष द्वारा जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को दिया गया, किसी को मंजूरी नहीं दी गई। जबकि परंपराएं और लोकसभा की कार्यवाही में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया गया। जब सत्ता पक्ष कांग्रेस को 'गद्दार' कहता है, तब वह सदन की मर्यादा है? और जब विपक्ष उसका जवाब देना चाहता है, तब उसे 'आउट ऑफ प्रोसीडिंग' बताकर रोक दिया जाता है। तो यह किस तरह की निष्पक्षता है? विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष का व्यवहार निष्पक्ष एवं मध्यस्थता वाला नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आसदी का व्यवहार

सत्ता पक्ष के रक्षक का है। पिछले वर्षों में जिस तरह से बिल और कानूनों को बिना किसी चर्चा के हो हल्ले में पास कर दिया गया। यही कारण है कि विपक्ष ने अब अविश्वास प्रस्ताव जैसा असाधारण कदम उठाने का मन बनाया है। पिछले 76 सालों में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन बार लाया गया है। चौथी बार ऐसी स्थिति बना जाये अपने आप में असाधारण और चिंताजनक है। संविधान के अनुसार, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब विपक्ष यह मान ले कि अध्यक्ष सदन की निष्पक्षता बनाए रखने में असफल हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत है। महिला सांसदों ने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी नाराजी जताई है। जो यह दर्शाती है, असंतोष केवल एक दल अथवा एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है, पिछले कई वर्षों में सदन के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। संसद की कार्यवाही बार-बार ठप होना अब सामान्य हो गया है। इसका लाभ उठा कर सत्ता पक्ष बिल पास कर लेती है। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बजाय बार-बार कार्यवाही स्थगित होना, अध्यक्ष द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाता है। जबकि नियमों के अनुसार विपक्ष की आवाज को अध्यक्ष का संरक्षण मिलना चाहिए। आसदी की इस कार्रवाई से लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। इतिहास गवाह है, जब-जब अध्यक्ष ने निष्पक्षता दिखाई,

तब-तब विपक्ष ने भी मर्यादा का पालन किया है। जब कुर्सी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ता है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच गई है, अध्यक्ष का आसन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। वर्तमान स्थिति केवल ओम बिरला या लोकसभा अध्यक्ष के पद या बजट सत्र की नहीं है, यह उस संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपरा की परीक्षा है जिसे भारत के संसदीय लोकतंत्र ने कई दशकों में गढ़ा गया है। यदि अध्यक्ष की निष्पक्षता पर विश्वास उठता है, तो केवल विपक्ष नहीं, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान भी कमजोर होता है। आवश्यकता इस बात की है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की गरिमा को पुनः स्थापित करें। सत्ता और विपक्ष, दोनों के लिए समान नियम और समान अवसर सुनिश्चित करें। विपक्ष के पास बहुमत नहीं होता है इसलिए उसे संरक्षण की जरूरत होती है। सत्ता पक्ष की दायीरगी से अध्यक्ष ही विपक्ष को संरक्षण दे सकता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास के सहारे चलता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आवाग की आवाज को सदन में लेकर आते हैं। सत्ता पक्ष से ज्यादा वोट विपक्ष के पास होते हैं। विपक्ष सत्ता दृढ़ हुआ होता है, इसलिए सत्ता पक्ष राज करता है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष को इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। लोकसभा के अध्यक्ष भले बहुमत से चुने जाते हों, लेकिन अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभी सदस्यों के अध्यक्ष होते हैं।

पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं दालें

इस दिवस की घोषणा के बाद से 2019 से यह निरंतर मनाया जा रहा है। इसकी प्रेरणा 2016 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष से मिली थी, जिसने पहली बार वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट किया कि दालें केवल पारंपरिक भोजन नहीं, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं। दलहन, यानी फलीदार पौधों से प्राप्त सूखे और खाने योग्य बीज, सदियों से मानव आहार का आधार रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये भोजन की रीढ़ रहे जबकि आधुनिक समय तक कुछ क्षेत्रों में इन्हें साधारण या कम मूल्य वाला भोजन समझा गया लेकिन पोषण विज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज यह स्वीकार किया जा चुका है कि दालें उच्च गुणवत्ता वाले पौध-आधारित प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनके साथ मिलने वाला आहार फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। आपरन, जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम और बी-विटामिन्स जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी बनाते हैं। कम वसा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। पर्यावरण की दृष्टि से दालों का महत्व और भी व्यापक है। इन्में मिट्टी में नाइट्रोजन सांद्रता को स्थिर करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जिससे खेतों

की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। यही कारण है कि बदलते जलवायु परिदृश्य में दलहन को जलवायु-अनुकूल और भविष्य की फसल माना जा रहा है। सीमित संसाधनों और अनिश्चित मौसम के दौर में ये फसलें किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनती जा रही हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी दलहन की भूमिका निर्णायक है। तेजी से बढ़ती आबादी, कुपोषण और जलवायु अस्थिरता के बीच दालें सस्ती, सुलभ और पोषण से भरपूर समाधान प्रस्तुत करती हैं। भूखमुक्त समाज, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास जैसे वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने में इनका योगदान प्रत्यक्ष और प्रभावी है। भारत में विश्व दलहन दिवस का महत्व केवल एक वैश्विक तिथि तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह देश की कृषि परंपरा, पोषण दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ जाता है। भारत न केवल विश्व के प्रमुख दलहन उत्पादक और उपभोक्ताओं में अग्रणी है बल्कि यहां की खाद्य संस्कृति में दाल को संतुलित आहार की आत्मा माना गया है। दाल-चावल, दाल-रोटी और खिचड़ी जैसे सरल, सुलभ और पौष्टिक भोजन सदियों से भारतीय समाज में स्वास्थ्य, सादगी और सहजीवन के प्रतीक रहे हैं।

दलहन केवल थाली की शोभा नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा की मजबूत आधारशिला हैं। इन्में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कुपोषण से लड़ने और स्वास्थ्य सुधारने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेषकर शाकाहारी आबादी के लिए दालें सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद प्रोटीन स्रोत हैं। कुल मिलाकर, यह दिवस किसानों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। दलहन आधारित फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिीकरण के कारण रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। परिणामस्वरूप किसानों की लागत कम होती है और आय में स्थिरता आती है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के दौर में दलहन खेती पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है। उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर अपने भोजन विकल्पों पर पुनर्विचार करने का संदेश देता है, अधिक पौध आधारित, स्थानीय और पोषण-संपन्न आहार की ओर लौटने का आह्वाण। दालें यह सिद्ध करती हैं कि सादगी में भी उत्कृष्टता छिपी होती है। यदि नीति-निर्माता, किसान और उपभोक्ता मिलकर दलहनों को प्राथमिकता दें तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, तीनों को एक साथ मजबूती मिल सकती है। सच यही है कि छोटे-छोटे बीजों मिलकर एक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की नींव रखते हैं।



लंबाई के अनुसार कपड़ों का करें चयन

अगर आपकी लंबाई कम है तो आप को इस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिये। कपड़े ऐसे हों जिनमें वर्टीकल पट्टियां हों। इसका कारण यह है कि हॉरीजौन्टल पट्टियों में आपकी लंबाई कम लगेगी। आप मोटी या पतली वर्टीकल पट्टियों को

पहन सकती हैं। केवल फैशन के पीछे न भागें। स्कर्ट, क्रॉप पैट जैसी चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि आप ऐसी चीजें पहनकर और छोटी लगेंगी।

एकिल तक की पट्टियों को कहीं बाय बाय-
एकिल तक की पट्टियों वाले कपड़ों

और जूतों को आप अपने से दूर रखें क्योंकि इससे आप और छोटी लगेंगी। अगर आपको एकिल तक की पट्टियों वाले फुटवियर पसंद हैं तो उसमें हील जरूर हों।

अगर आप बड़े आकार के बैग का इस्तेमाल करती हैं तो उसे बदल दें। ज्यादा बड़े आकार के बैग को कैरी करने से आपकी हाइट और कम लगती है। इसलिए आप ऐसा बैग लें जिस में आप अच्छी लगें।

शर्ट ड्रेस से दूर रहें-

जिनके पैरों की लंबाई ज्यादा होती है उन पर शर्ट वाली ड्रेस अच्छी लगती है। शर्ट वाली ड्रेस का कोई अपना आकार नहीं होता है इसलिए ये आपको चकोर से लुक देता है जो आप पर थोड़ा अजीब लग सकता है।

गहरी कट के कपड़े पहनें-

दी आकार की नेकलाइंस वाले

कपड़े आप पर अच्छे भी लगेंगे और उसमें लंबी भी लगेंगी। अगर आपकी हाइट कम है तो ये अगर आपको मेक्सी ड्रेस पसंद है तो आप उसे पहन सकती हैं। लेकिन फिटिंग को ध्यान में रखते हुए वो नीचे की तरफ से थोड़ा कसा हुआ हो। इसमें आप स्मार्ट और स्टाइलिश लगेंगी।



घरेलू उपाय से ठीक होंगी फटी एड़ियां

पैरों की खूबसूरती भी जरूरी है पर कई बार धूल लगने से एड़ियां फट जाती हैं। इससे पैरों की खूबसूरती कम हो जाती है पर फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए कहीं बाहर जाने की बजाय कुछ घरेलू उपायों को करना ठीक रहता है।

नींबू रहेगा फायदेमंद

नींबू का इस्तेमाल करके फटी एड़ियों को सही किया जा सकता है। इसके लिए नींबू के रस को गर्म पानी में मिलाएं और 10 से 15 मिनट तक पैरों को पानी में डुबोए रखें। इसके बाद एड़ी को प्यूमिक स्टोन से साफ करें और फिर पैरों को धो कर तौलिये से पोछ लें।

गुलाब जल और ग्लिसरीन

ग्लिसरीन और रोजवॉटर (गुलाब जल) फटी एड़ियों को सही करने और एड़ियों को मुलायम करने में मदद करता है। सबसे पहले ग्लिसरीन और रोजवॉटर को बराबर मात्रा में लेकर पेस्ट तैयार कर लें। रात को सोने से पहले इस पेस्ट को एड़ियों पर लगा लें।

वनस्पति तेल

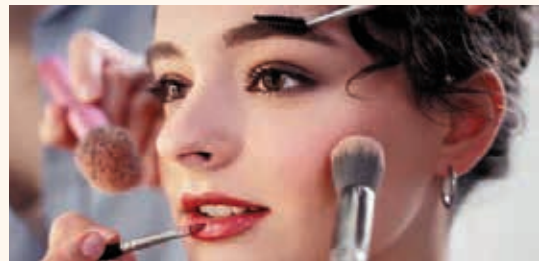
वनस्पति तेल भी फटी एड़ियों के लिए काफी सही रहता है। वनस्पति तेल में जैतून, नारियल, तिल या किसी भी तरह का वनस्पति तेल लेकर रात को सोने से पहले एड़ियों में मसाज करने से फायदा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले पैरों को गर्म पानी में भिगोकर रखें और बाद में स्कब कर के सुखा लें। इसके बाद वनस्पति तेल को एड़ी और तलवों पर लगाकर मोजे पहनकर सो जाएं।

नीम

नीम भी फटी एड़ियों को सही करने में कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को हल्दी के साथ मिक्स कर के पेस्ट तैयार कर लें।

सुंदर दिखने के लिए अपनाएं ये तरीके

सुंदरता के लिए अपनायें ये तरीके। इस प्रकार आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकती हैं। आंखों की सुंदरता के लिए गोल्ड आई शेडो का प्रयोग करें। आंखों पर गहरे रंग के आई पेंसिल का प्रयोग करें। आप इलेक्ट्रिक ब्लर आईलाइनर के इस्तेमाल करने से भी अच्छा लुक पा सकती हैं। रात के समय ब्लशर रंगों का होठों के रंगों से मेल जरूरी नहीं है, लेकिन टोन का रंग सामान्यता एक जैसा होना चाहिए। यदि आपने नारंगी लिपस्टिक लगाई है तो गुलाबी ब्लश से दूर रहिए। आप लिपस्टिक में लाल गहरे लाल रंग की शेड की लिपस्टिक का प्रयोग कर सकती हैं। गहरा गुलाबी रंग भी काफी आकर्षक लगेगा। ज्यादातर त्वचा के रंगों में नारंगी शेड भी काफी सराही जाती है। उमस भरे मौसम में उड़ी लुक पाने के लिए फेस पर ब्राजिंग और हाइलाइटिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ ही फेस पर बेस ब्लेंडेड करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही टोनिंग भी बेहद अनिवार्य है। इसके लिए आप किसी मलमल के कपड़े में बर्फ डालकर अपने चेहरे पर हल्के-हल्के से मल सकती हैं। इससे पोर्स तो बंद हो ही जाएंगे और मेकअप भी देर तक टिका



रहेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइश्चराइजिंग लोशन से कुछ मिनट तक हल्के-हल्के मसाज कर सकती हैं।

अपनी त्वचा से अनचाहे दाग-धब्बे छुपाने के लिए कंसीलर का यूज कर सकती हैं। कंसीलर को अपनी उंगली में लेकर प्रभावित स्थान पर हल्के से थपथपा कर लगाएं, जिससे कंसीलर आपकी स्किन में अच्छे से समा जाए। अगर आपकी ड्रेस ज्यादा भारी नहीं है तो बहुत डार्क मेकअप ना करें, बल्कि लिपस्टिक और आई शेड्स में हल्के रंगों के उपयोग करें। आंखों पर मस्कारा लगाएं। आप लिविड काजल की जगह पेंसिल वाला काजल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी ड्रेस हैवी है तो लिक्विड काजल का इस्तेमाल करें और मस्कारा लगाएं। साथ ही लिपस्टिक और आई शेड्स डार्क गहरे रंग के इस्तेमाल करें। चाहे तो होठों के लिए लिक्विड लिप ग्लॉस का उपयोग भी कर सकती हैं। ड्रेस के बाद बारी आती है हेयर स्टाइल की। आप चाहे किनता भी अच्छा मेकअप कर लें या ज्वेलरी पहने जब तक आपका हेयर स्टाइल सही नहीं है आपका लुक परफेक्ट नहीं लग सकता। इसलिए अपने बालों को अच्छा सा हेयर स्टाइल दें।

अगर आपके बाल छोटे हैं तो उन्हें खुला ही छोड़ दें। खुले बालों में भी काफी स्टाइल दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने बालों को सामने की ओर से पक दे सकती हैं या विलप्स की मदद से सामने के बाल थोड़े-थोड़े लेकर पीछे की ओर घुमाकर पिनअप कर सकती हैं। ट को एड़ियों पर लगा लें। इस पेस्ट को 1 घंटे लगाकर रखें और फिर पानी से साफ कर लें।

नींद पूरी न होना महिलाओं की सेहत पर डाल सकता है गहरा असर



अच्छी सेहत पाना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है और चुनौती भी। हालांकि दुनियाभर में जिस तेजी से डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज-किडनी की बीमारियां, बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। जब बात महिलाओं की सेहत की आती है तो ये चिंता और भी बढ़ जाती है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि महिलाओं की सेहत लगातार चुनौतियों से जुझ रही है। करियर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं दे पातीं। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, अनियमित



खानपान, शारीरिक गतिविधियों में और बढ़ते मानसिक तनाव ने समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया है। पर्याप्त पोषण की कमी महिलाओं में एनीमिया का खतरा बढ़ाती जा रही है, भारत में 57% से अधिक महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं।

इन समस्याओं के अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक छोटी सी लापरवाही को लेकर भी सभी महिलाओं को सावधान करते हैं, जो धीरे-धीरे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को खराब करती जा रही है।

नींद की कमी महिलाओं की सेहत का दुश्मन महिलाओं में नींद की समस्या या रात में देर से सोने की आदत को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए बहुत हानिकारक मानते हैं। नींद की कमी एक साइलेंट खतरे के रूप में उभर रही है। देर रात तक जागना, मोबाइल और स्क्रीन टाइम बढ़ना और स्ट्रेस के कारण महिलाओं की नींद पूरी नहीं हो पाती।

अध्ययनों से पता चलता है कि रात में 8 घंटे से कम की नींद हार्मोनल असंतुलन के साथ महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को प्रभावित कर सकती है। कम उम्र में ही

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) मोटापा, डायबिटीज, थायरॉइड और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर नींद विकारों या देर से सोने की आदत को जिम्मेदार पाया गया है।

हार्मोनल असंतुलन और पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं नींद पूरी न होना महिलाओं के हार्मोनल सिस्टम को सबसे पहले प्रभावित करता है। नींद के दौरान शरीर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेलाटोनिन जैसे जरूरी हार्मोन को संतुलित करता है।

जब महिलाएं देर रात तक जागती हैं या 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पातीं, तो इससे हार्मोनल साइकिल बिगड़ जाती है।

इसका सीधा असर पीरियड्स पर पड़ता है, जिससे अनियमित माहवारी, ज्यादा दर्द, हैवी ब्लॉडिंग या पीरियड्स का देर से आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

लगातार नींद की कमी पीसीओएस के खतरे को भी बढ़ाती है, जिसके कारण प्रजनन स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लग जाता है। इससे गर्भधारण में परेशानी और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं।



नाखूनों को ऐसे बनाएं सुंदर

लड़कियों को लंबे-लंबे नाखून रखना पसंद होता है, लेकिन इन्हें लंबा करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आसान होता तो हर किसी के हाथ में लंबे नाखून देखने को मिलते। कई लड़कियों के नाखून लंबे होते हैं तो सुंदर नहीं होते। नाखूनों को सुंदर और लंबा इस प्रकार बनायें।

बहुत सारी महिलाओं के नाखून बढ़ते तो हैं लेकिन कमजोर होने के चलते जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा। आपको कुछ ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जिनसे आपको पोषक तत्व मिलें।

संतरे का रस

संतरे के रस को दस मिनट

नाखून लंबे करने के लिए रोजाना ऑलिव ऑयल से नाखूनों की मालिश करें। विटामिन ई से भरपूर ऑलिव ऑयल नाखूनों को पोषण प्रदान करता है और खून का पलो नाखूनों तक बढ़ाता है जिससे नाखून तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं।

लहसुन

नाखूनों को बढ़ाने के लिए लहसुन एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। लहसुन को दो टुकड़ों में काट कर उसे 10 मिनट तक अपने नाखूनों पर रगड़ें। ऐसा करने से आपके नाखून कुछ ही दिनों में अच्छे खासे बढ़ जाएंगे।

